

शिव सेना के पर्याय हैं राड़ा और खड़नी

अनुराग चतुर्वेदी

मराठी के जाने-माने उपन्यासकार भाऊ पाध्ये का एक बहुचर्चित उपन्यास है 'राड़ा'। यह उपन्यास सामाजवादियों के गढ़ गोरेगांव (मुंबई का उपनगर) में अण्णेगिरी पात्र के आसपास रचा गया है। छोटी-सी फैंक्टरी चलाने वाले अण्णेगिरी का पुत्र मंदार अति क्रांतिकारी हो जाता है, और हिंसा को सही मानने लगता है। 'राड़ा' उपन्यास में शिवसेना की कई हिंसक तकनीकें उन्होंने कथा के माध्यम से बताई, पर नई दिल्ली के नवीन महाराष्ट्र सदन में ठाणे के सांसद 52 वर्षीय राजन विचारे ने जो कुछ किया, वह भाऊ भी नहीं सोच पाये थे।

शिवसेना का रक्तबीज ही 'राड़ा' है। ज्यादातर शक्तिहीन अल्पसंख्यक, छोटे-मोटे व्यापारी, बाहर से आए मेहनतकश, अन्य भाषा-भाषी पहचान प्रकट करने वाले असहाय नागरिक (लुंगी पहना दक्षिण भारतीय या दाढ़ी रखा पुणे का इंजीनियर)। इनके अलावा अन्य 'सॉफ्ट टारगेट' हैं लेखक, पत्रकार, संगीतकार, क्रिकेट खिलाड़ी, दुकानों के मैनेजर (मालिक कभी नहीं)।

'राड़ा' के अलावा दूसरा मूल तत्व है 'खड़नी' (जबरन पैसा वसूली) शिवसेना के नेता बिल्डरों, छोटे उद्योगपतियों, दुकानदारों और विवादों में फंस जाने वाले नागरिकों को इसकी चपेट में ले लेते हैं। राड़ा, खड़नी शिवसेना के पर्याय हैं। मुंबई में कांग्रेस के लम्बे शासनकाल में शिवसेना के नेताओं को यह विश्वास हो गया है कि हमारे द्वारा फैलायी गई हिंसा कानून-व्यवस्था, भारतीय कानून के ऊपर है। यदि स्कूल में कोई हेडमास्टर प्रवेश देने में अपनी असमर्थता दिखा रहा है तो उसको पीटो, उसका मंह काला करो, कोई रिक्शावाला रुक नहीं रहा है तो उसे आगे भाग कर 'कान के नीचे झापड़रसीद करो'। इस काम में न केवल पुरुष शिवसैनिक बल्कि महिला शिवसैनिक भी आगे रहती हैं।

शिवसैनिकों ने मराठी सांध्य दैनिक महानगर पर जो हिंसक हमला किया हो, विपक्षी दल के नेता के रूप में स्थापित पूर्व शिव सैनिक छगन भुजबल के घर पर 'खतरनाक' हमला हो और राजन विचारे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने शिवसैनिक खोपकर के लोकप्रभा में साक्षात्कार देकर (तब लोकप्रभा के संपादक संजय राऊत थे) कहा था- गद्दारा ना देहांत शासन (गद्दारों को मृत्यु)। प्रसिद्ध उपन्यासकार वीएस नायपाल ने शिवसैनिक विट्ठल चव्हाण के ऊपर एक शानदार आलेख लिखा है। मुंबई में एक समय कपड़ा मिलों के हृदय प्रदेश गिरण गांव में विट्ठल चव्हाण का दबदबा था, जो राजनीतिक तो कतई नहीं था। विट्ठल चव्हाण शिवसेना के विधायक बन गये और एक गैंगस्टर गुरु साटम ने दनकी हत्या करवा दी। निखिल वागले को 'केलिडोस्कोप' लिखने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा ने विशेषाधिकार का मामला

मानते हुए एक दिन की सजा भी दी थी। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी की राजनीतिक हत्या हुई थी, दूसरी हत्या मुंबई में साम्यवादी विधायक कृष्णा देसाई की हुई, जिसके बाद मुंबई में साम्यवादियों की यूनियनों की जगह शिवसेना की यूनियनें आने लगीं। राड़ा, खड़नी और गंधीर अपराध के बाद ज्यादातर शिवसैनिकों और उनके नेताओं से संसदीय अनुकरणीय आचरण की अपेक्षा रखना सही नहीं होगा।

उपवास को महात्मा गांधी आत्मशुद्धि का जरिया मानते थे। वे न केवल अपनी बात मनवाने के लिए उपवास करते थे, बल्कि अपने कलुष को धोने के लिए उपवास रखते थे। ईराम शर्मिला मणिपुर में सेना द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ उपवास रखती हैं तो कई लोग सरकार द्वारा उन्हें नली के जरिए जबरदस्ती खिलाने के खिलाफ रहते हैं। महाराष्ट्र सदन के अरशद जुबैर भी रमजान के पवित्र महीने में श्रद्धा से यदि अपना रोजा रख रहे थे, तो उनके साथ यह जबरदस्ती थी।

शिवसैनिकों ने हमेशा असंगठित, कमजोर या फिर बुद्धिजीवियों के सृजनात्मक कार्यों के प्रकाशन, प्रदर्शन को राड़ा (उपद्रव या उदंडता) करके रोका है। सभा में आगे की पंक्ति में बैठकर कुर्सियां फेंकना, मुख्य वक्ता को बोलने से रोकना, न रुकने पर उसे हवा में फेंक जमीन पर गिरा देना, मुंह को काला करना, मुंह में हाथ ठूस देना। औरतें चूड़ियां

शिवसैनिकों ने हमेशा असंगठित, कमजोर या फिर बुद्धिजीवियों के सृजनात्मक कार्यों के प्रकाशन, प्रदर्शन को राड़ा (उपद्रव या उदंडता) करके रोका है। सभा में आगे की पंक्ति में बैठकर कुर्सियां फेंकना, मुख्य वक्ता को बोलने से रोकना, न रुकने पर उसे हवा में फेंक जमीन पर गिरा देना, मुंह को काला करना, मुंह में हाथ ठूस देना। औरतें चूड़ियां

पहनाने, तमाचा मारने, अपशब्दों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित होती हैं। ये कार्यकर्ता भीड़ का रूप लेने में माहिर होते हैं।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी इलाके के कोंकणी मराठे राजन विचारे अपने इलाके (ठाणे) के मतदाताओं को तीर्थयात्राएं कराने के लिए जाने जाते हैं। शिवसेना-भाजपा चुनाव प्रचार के पूर्व शिरडी और पुणे के अष्ट विनायक को यात्राएं कराने में आगे रहते हैं। ज्यादातर तीर्थयात्राओं का खर्चा राजनीतिक दल या

उनके समर्थक ही उठाते हैं।

शिवसेना को यदि उत्तरी भारतीय पाठकों को समझाना हो तो इसे संघ परिवार के उग्र बजरंग दल के रूप में जाना जा सकता है। शिवसेना की इतने सारे छोटे-बड़े राड़े करने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी के कारण ही बढी है। महाराष्ट्र सदन की घटना भी एक सप्ताह बाद 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित होने के बाद समाज में जानी गई, पर महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार को इस घटना की जानकारी पूर्व में थी। पर उसने इन असंसदीय और अपराधिक व्यवहार करनेवाले सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं की। शिवसेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के कार्यकाल में घोषित किया था कि वे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मुंबई और महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में आने नहीं देंगे। चव्हाण ने तगड़ी पुलिस कार्रवाई और शासन का बल दिखा कर इस विरोध को दबा दिया था। शिव सैनिक पुलिस के बल से भी बहुत डरते हैं, परंतु महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री की भूमिका संदिग्ध नजर आती है।

शिवसेना के इस अविवेकी राड़ा प्रवृत्ति का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। शिवसेना क्या यह सोच रही है कि वह दिल्ली में भी राड़ा करके आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के मुकाबले ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी रह सकती है? इस झगड़े की जड़ में मुंबई के पूर्व आयुक्त सत्यपाल सिंह भी थे,

जिन्होंने चौधरी अजित सिंह को हरा कर भाजपा की सांसदी हासिल की है। भाजपा के सत्यपाल को चार कमरे और हमें रबड़ की रोटी। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अरशद जुबैर के रोजेदार मुसलिम होने पर असहज तो हैं, पर वे इस कल्पना से ही कांप रहे हैं कि यदि अरशद की जगह किसी शुक्ला, शर्मा या चौबे के साथ शिवसैनिकों ने यह आचरण किया होता तो यह मुद्दा मराठी बनाव हिंदीभाषी हो जाता।

शिवसेना को इस बार अपनी एक पुरानी आदत भी धोखा दे गई। राड़ा करने के पहले शिवसैनिक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मीडिया को भी सूचित करते हैं। भय की कार्रवाई दर्शकों में दहशत पैदा करेगी और भयादोहन राजनीतिक ताकत देगा। विजय तेंदुलकर के घासीराम कोतवाल नाटक या सखाराम बाईडर का प्रदर्शन हो, शिवसैनिक मीडिया साथ लाकर उपद्रव करते रहे हैं। महाराष्ट्र सदन में भी मराठी चैनल को बुलाया गया। यों बुलाया दूसरों को भी था, पर वे आए नहीं। शिवसेना को मीडिया को बुलाना इस बार मंहगा पड़ा और 'मी मराठी' चैनल राष्ट्रीय स्तर पर न केवल प्रसिद्धि पाया, बल्कि अमीर भी हुआ। शिवसेना को अब अपने तरीके बदलने होंगे, पर क्या व्यक्ति या राजनीतिक दल का डीएनए बदलता है? शिवसैनिकों की अगली हरकत ही इसका जवाब होगी।

-जनसत्ता से साभार

सम्पादक के नाम शहर वासियों का एक खुला पत्र

चुनावी आहट से पंजाबी बिरादरी का इमाम नींद से उठा

अपने आप को पंजाबी बिरादरी का इमाम व इंदिरा गांधी को बहन राजीव गांधी को भान्जा व सोनिया गांधी को बहू बतानेवाला पूर्व मंत्री ए.सी. चौधरी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लम्बी नींद से जागा है। रोजाना दर्जनों लोगों को फ़ोन करवा व अपने घर बुलाकर उनकी नींद उड़ा रहा है। उन्हें राहुल गांधी प्रियंका द्वारा चुनावों में चौधरी से सलाह मशवरा की झूठी मनघड़त कहानियां सुना कर पका रहा है। जबकि चौधरी के घर जाने वाले ब्लॉक वासी ए.सी.चौधरी की औकात भली-भांति जानते पहचानते हैं कि चौधरी झूठ का पुलिंदा है।

चौधरी के शुरूआती दौर में फ्रेंड्स सोशल वर्कर्स एसोसिएशन के स्वर्गीय मदनलाल भसीन, सरदार गुरुबचन सिंह, खमोश सरहदी, कन्हैया लाल खट्टक ने ए.सी. चौधरी को चुनाव लड़वाया और चौधरी पहली बार विधायक बना। उसके बाद ए.सी. चौधरी उन्ही लोगों को काटता गया जिनसे वे आगे बढा था।

चौधरी लोगों से ये कहते भी सुना गया है कि उसका बचपन डकोटा जहाज की सैर करके बीता है। चौधरी का घर 5 नम्बर एम ब्लॉक में है। जहां उनके सभी नाते-रिश्तेदार रहते हैं। जिन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उनका कुनबा पाकिस्तान में रहता था तो उनके आंगन में कितने डकोटा जहाज बंधे थे। वे बताते हैं कि डकोटा जहाज का तो मालूम नहीं उनके घर पर एक गधा (खोता) जरूर बंधा रहता था जिस पर (बनवारी) ए.सी. चौधरी अपने बाप कर्मचंद से जित करके बैठ जाता था।

फ़रीदाबाद के पंजाबियों के अलावा प्रदेश का पंजाबी समाज अच्छी तरह जानता है कि चौधरी ने सदैव पंजाबी कार्ड खेल कर राजनीति की है व अपना उल्लू सीधा किया है। पंजाबियों के नाम पर कभी 30 तो कभी 35 टिकट मांगने वाला ए.सी. चौधरी सिर्फ अपनी एक टिकट लेकर पूरे पंजाबी समाज को बेच देता है। जिसके चलते कई पंजाबी संगठन चौधरी के खिलाफ हो गये। पिछले विधान सभा चुनावों में ए.सी. चौधरी का पुतला तक उसके घर पर फूंक चुके हैं। पुतला फूंकते समय ए.सी.चौधरी के ब्लॉक वासियों ने भी बढ-चढ कर हिस्सा लिया था।

इतने साल ए.सी. चौधरी हरियाणा सरकार में मंत्री रहा है, उसके अपने मुहल्ले 'के' ब्लॉक के लोग चौधरी से पूछना चाहते हैं कि उसने कितने पंजाबियों को नौकरी लगवाया है।

चौधरी लोगों से ये कहते भी सुना गया है कि उसका बचपन डकोटा जहाज की सैर करके बीता है। चौधरी का घर 5 नम्बर एम ब्लॉक में है। जहां उनके सभी नाते-रिश्तेदार रहते हैं। जिन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उनका कुनबा पाकिस्तान में रहता था तो उनके आंगन में कितने डकोटा जहाज बंधे थे।

वह उन लोगों की एक लिस्ट सार्वजनिक करें। उन्ही के राज व उनकी सरकार के टाइम में उन्हीं के ब्लॉक का पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सबसे ज्यादा जुआ व सट्टा उन्हीं के ब्लॉक के युवा बच्चे खेल रहे हैं। करीबन 5 नं. एम ब्लॉक में आधा दर्जन घरों के बच्चें अवैध शराब बेच रहे हैं। क्या ये सब ए.सी. चौधरी को नहीं दिखता?

ए. सी. चौधरी के एक रिश्तेदार ने इनकी सहमति से अपने ही ब्लॉक के 5 एम 93 मकान, जो कि एक गरीब रिक्शा चलाने वाले का है, पर नाजायज कब्जा कर रखा है। उन्हीं की सरकार में 5 नं. में ब्याजखोरों, जुआरियों व सट्टेबाजों के जाल में फंसकर उन्हीं के ब्लॉक व क्षेत्र के नौजवान लड़कों ने आत्महत्या तक कर ली। चौधरी ने उन नौजवान लड़कों के चौथे उठालों में जाकर भाषणबाजी व मोमबत्ती जुलूस निकाल कर नेतागिरी तो कर ली पर क्या आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले दबंगों पर कोई कार्यवाही या कार्यवाही की मांग करी, कोई धरना प्रदर्शन गिरफ्तारी की मांग करी? चौधरी, ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जुआ सट्टा जमीनों पर कब्जा करने वाले ही तो चौधरी को अब चुनाव लड़वाते हैं। पिछलों चुनावों में जनता द्वारा नकारा जा चुका ए.सी. चौधरी इस बार फिर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान ए. सी. चौधरी की टिकट काटेगी या फिर जनता उसका पत्ता काटेगी?

तुर्की-ब-तुर्की

हमारा कहना है:-

□ हेमा मालिनी को सफ़ाई देने की जरूरत नहीं थी। उनके क्षेत्र मथुरा के लोग भी जानते हैं कि न वे निर्वाचन क्षेत्र में आई हैं और न ही आगे आयेंगी। उनके पति धर्मेन्द्र जो बीकानेर से सांसद रहे हैं, भी कभी मुड़कर अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं गये।

□ वैसे निर्वाचन क्षेत्र जाकर करना भी क्या है? लोगों ने तो मोदी को वोट दिया था। जहां जाना है मोदी जायें। हेमा ने तो भाजपा के लिये चुनाव में ग्लैमर लाना था, सो ला दिया। अब 5 साल बाद देखेंगे। भाजपा को तब भी हेमा की जरूरत हुई तो निर्वाचन क्षेत्र बदल देंगे। आखिर मथुरा की जनता ने तो ग्लैमर देख ही लिया। अगली बार कहीं और के लोग ग्लैमर देख लें।

□ सवाल यह भी बनता है कि जो

भाजपा के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा रहे हैं, वही कौन सा तीर मार ले रहे हैं। दिल्ली के सातो सांसद दिल्ली में ही रहते हैं। पर यहां की जनता बिजली, पानी, मंहगाई, भ्रष्टाचार आदि को लेकर त्रस्त हो रही है।

□ वैसे भी भाजपा ने अपने तमाम सांसदों को निर्देश दे रखा है कि मुद्दों पर बोलने का काम पार्टी प्रवक्ताओं का है न कि सांसदों का। संसद में भी किसे बोलना है और कितना बोलना है, पार्टी ही तय करती है। पार्टी का मतलब है मोदी या थोड़ा सा अमित शाह। तो अब उसमें हेमा कहां से आ गयीं।

□ हेमा मालिनी से शिकायत तो मथुरावासी तब करें जब उनका ग्लैमर काम न करे। और कोई दावा उनका न बनता है और न उन्होंने किया ही था।

कासनी का तबादला, समस्या जस की तस

पेज एक का शेष

लेकिन असल में यहां केवल फ़र्जी बिलिंग के द्वारा करोड़ों रुपये के घोटालों के अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं। तमाम स्कूलों, कॉलेजों व दफ़्तरों में चलने वाला कम्प्यूटरों का धंधा इसी के मार्फ़त चलता है। जाहिर है मोटी लूट कमाई कर चुके सांगवान पर मुख्यमंत्री पूरा भरोसा कर सकते हैं। इसी भरोसे पर खरा उतरने की जल्दबाजी में दफ़्तर का चार्ज लेन-देन की औपचारिकता निभाये बिना ही सांगवान अगली सुबह 9 बजे ही कासनी के दफ़्तर में आ घुसे और उनके कम्प्यूटर को खंगालने के प्रयास में उसे हँग कर दिया क्योंकि बिना पासवर्ड के कम्प्यूटर खुल ही नहीं सकता था। कासनी के कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी 3 दिन तक मुख्य सचिव के दफ़्तर में बैठा कर पूछताछ होती रही, परन्तु निकला कुछ नहीं।

बड़ा सवाल अब यह है कि क्या अशोक सांगवान सम्बन्धित फ़ाइल पर प्रदीप कासनी के लिखे हुए एको काट पायेंगे? क्या वे राज्यपाल को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में असल तथ्यों को छिपा पायेंगे? इनसे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्यपाल केवल वही सब देखने को बाध्य हैं जो अशोक सांगवान के माध्यम से हरियाणा सरकार उन्हें दिखाना चाहेगी???

राज्यपाल सरकार के मुखिया हैं। वे तथ्यों की सही जानकारी एवं वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करने का पूरा अधिकार भी रखते हैं। इसके लिये राज्य सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करने का पूरा संवैधानिक अधिकार रखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अशोक सांगवान मुख्यमंत्री हुड्डा की कटी हुई नाक को बचाने के लिये अपना कुछ दांव पर लगाने को जोखिम उठाते हैं।



“मैं लोकसभा चुनाव के बाद अमेरिका चली गयी थी, इसलिये अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सकी हूँ। लेकिन इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ा।”